● वर्ष : 04 ● अंक : 04 ● सितंबर 2025 ● हिन्दी मासिक पत्रिका ₹ 40/-

RNI : CHHHIN 2022/86325

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

- निवेदन -

स्वतंत्र बोल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। फ़ोन और ई-मेल पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र से घटित कोई घटना, समाचार, या अन्य कोई गतिविधि जो पत्रिका में प्रकाशन योग्य हो.. तो उसे भी भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय हिन्दी मासिक पत्रिका
तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट को निर्भीक और
जनपक्षीय पत्रकारिता के लिये आर्थिक रूप से सहयोग करें।

बंधन बैंक
बैंक खाता नंबर- 20100031810292
आईएफएससी कोड- BDBL0001958

SB स्वतंत्र बोल

संपादक स्वतंत्र बोल, शॉप नं. 258, लालगंगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स, घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.)
97543-74333, bolswatantra@gmail.com
www.swantantrabol.com

RNI : CHHHIN 2022/86325

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

वर्ष : 04, अंक : 04, सितम्बर 2025

प्रेरणास्त्रोत
स्व. जीवन गिरि गोस्वामी

संपादक
राहुल गिरि गोस्वामी

कानूनी सलाहकार
आनंद मोहन तिवारी
दिनेश मिश्रा

प्रचार-प्रसार-विज्ञापन
शेखर सागर

ले-आउट/डिजाइन
द्वारिका प्रसाद साहू

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक
राहुल गिरि गोस्वामी द्वारा
शॉप नं. 258, सेकण्ड फ्लोर
लालगंगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स, घड़ी चौक
रायपुर (छ.ग.) पिन-492001 से प्रकाशित
एवं सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001 से मुद्रित।
सम्पादक - राहुल गिरि गोस्वामी

रजिस्टर्ड कार्यालय
शॉप नं. 258, सेकण्ड फ्लोर
लालगंगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स, घड़ी चौक
रायपुर (छ.ग.) पिन-492001
Email : Bolswatantra@gmail.com
Phone : 9754374333

(समस्त न्यायालीन प्रकरणों के
निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।)

संघ की सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है : डॉ. मोहन भागवत 03

सहकार भारती बुनकर प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अधिवेशन... 07

रायपुर से राजिम जाना हुआ आसान 09

केन्द्र सरकार की अभिनव पहल 11
'प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना'

आदि कर्मयोगी लाएंगे जनजातीय गांवों में 18
जमीनी बदलाव : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

हिन्दी दिवस : हिन्दी की सरलता और... 22

तवांग तीर्थ-यात्रा : भारत की आत्मा 30

वार्ता से रास्ता निकले 32

मोदी की गारंटी पूरे करने की चुनौती..

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार अंततः हो गया। साल भर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, नए और पुराने विधायकों के बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने रस्साकसी जैसा माहौल रहा। पार्टी का माहौल देख नए विधायक भी स्वयं को मंत्री बनाने एड़ीचोटी का जोर लगाते रहे, पर पार्टी संगठन ने पहले ही उन नामो को तय कर रखा था। आरंग के विधायक खुशवंत गुरु, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल और दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव पर पार्टी संगठन ने मुहर लगाया। अब जिम्मेदारी सरकार को काम करने की है। शुरुआती दो साल सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगा दिया,गारंटी के कितने वादे पूरे हुए सरकार जानती है। दिसंबर में सरकार को बने दो साल पुरे हो जायेंगे, उसके बाद सरकार के पास इस कार्यकाल के सिर्फ 2 साल बचेंगे, ऐसे में सरकार को अपने किये हुए अधूरे वादों को पूरा करने जुटना होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य वादों को पूरा किया पर अनेक वादे अब भी ऐसे है जो पूरे नहीं हुए है। ऐसे में उन वादों को तेजी से पूरा करने और आम लोगो तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

सरकार के दो सालो में ही नेक संगठनों के वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा, आम तौर पर चुनावी साल में ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे में जरुरी है कि मोदी की उस गारंटी को पूरा किया जाए जिसे चुनाव के दौरान वचन पत्र के रूप में बताया गया था।

(राहुल गोस्वामी)

संघ की सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है : डॉ. मोहन भागवत

संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ का निर्माण भारत को केंद्र में रखकर हुआ है और इसकी सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है। संघ कार्य की प्रेरणा संघ प्रार्थना के अंत में कहे जाने वाले 'भारत माता की जय' से मिलती है। संघ के उत्थान की प्रक्रिया धीमी और लंबी रही है, जो आज भी निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि संघ भले हिन्दू शब्द का उपयोग करता है, लेकिन उसका मर्म 'वसुधैव कुटुंबकम्' है। इसी क्रमिक विकास के तहत गांव, समाज और राष्ट्र को संघ अपना मानता है। संघ कार्य पूरी तरह स्वयंसेवकों द्वारा संचालित होता है। कार्यकर्ता स्वयं नए कार्यकर्ता तैयार करते हैं।

दिल्ली के विज्ञान भवन में '100 वर्ष की संघ यात्रा – नए क्षितिज' विषय पर तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है।

व्याख्यानमाला के उद्देश्य पर मोहन भागवत जी ने कहा कि संगठन ने विचार किया कि समाज में संघ के

बारे में सत्य और सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। वर्ष 2018 में भी इसी प्रकार का आयोजन हुआ था। इस बार चार स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक संघ का सही स्वरूप पहुँच सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की परिभाषा सत्ता पर आधारित नहीं है। हम परतंत्र थे, तब भी राष्ट्र था। अंग्रेजी का 'नेशन' शब्द 'स्टेट' से जुड़ा है, जबकि भारतीय राष्ट्र की अवधारणा सत्ता से जुड़ी नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद देश में उपजी विचारधाराओं का विकास पर कहा कि 1857 में स्वतंत्रता का पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन उससे नई चेतना जागी। उसके बाद आंदोलन खड़ा हुआ कि आखिर कुछ मुट्ठीभर लोग हमें कैसे हरा सके। एक विचार यह भी उभरा कि भारतीयों में राजनीतिक समझ की कमी है। इसी आवश्यकता से कांग्रेस का उदय हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वह वैचारिक प्रबोधन का कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकी। यह दोषारोपण नहीं, बल्कि तथ्य है। आजादी के बाद एक धारा ने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया, वहीं दूसरी धारा ने अपने मूल की ओर लौटने की बात रखी। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के इस विचार को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार और अन्य महापुरुषों का मानना था कि समाज के दुर्गुणों को दूर किए बिना सब प्रयास अधूरे रहेंगे। बार-बार गुलामी का शिकार होना इस बात का संकेत है कि समाज में गहरे दोष हैं। हेडगेवार जी ने ठाना कि जब दूसरों के पास समय नहीं है, तो वे स्वयं इस दिशा में काम करेंगे। 1925 में संघ की स्थापना कर उन्होंने संपूर्ण हिन्दू समाज के संगठन का उद्देश्य सामने रखा।

हिन्दू नाम का मर्म समझाते हुए सरसंघचालक जी ने स्पष्ट किया कि 'हिन्दू' शब्द का अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव है। यह नाम दूसरों ने दिया, पर हम अपने को हमेशा मानव शास्त्रीय दृष्टि से देखते आये हैं। हम मानते हैं कि मनुष्य, मानवता और सृष्टि आपस में जुड़े हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। हिन्दू का अर्थ है समावेश और समावेश की कोई सीमा नहीं होती। सरसंघचालक जी ने कहा कि हिन्दू यानी क्या - जो इसमें विश्वास करता है, अपने अपने रास्ते पर चलो, दूसरों को बदलो मत। दूसरे की श्रद्धा का भी सम्मान करो, अपमान मत करो, ये परंपरा जिनकी है, संस्कृति जिनकी है, वो हिन्दू हैं। हमें संपूर्ण हिन्दू समाज का संगठन करना है। हिन्दू कहने से यह अर्थ नहीं है कि हिन्दू वर्सेस ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 'हिन्दू' का अर्थ है समावेशी।

स्वस्थ और नशामुक्त भारत के लिए 'नमो युवा रन', युवाओं में दिखा जोश

देश का हर युवा स्वस्थ हो, समर्थ हो, सक्षम हो, इसके लिए नशामुक्त भारत जरूरी : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने झंडा लहराकर 'नमो युवा रन' का किया आगाज, विजेताओं को पुरस्कार बांटे

उप मुख्यमंत्री ने झंडा लहराकर 'नमो युवा रन' का किया आगाज, विजेताओं को पुरस्कार बांटेउप मुख्यमंत्री ने झंडा लहराकर 'नमो युवा रन' का किया आगाज, विजेताओं को पुरस्कार बांटे

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वस्थ और नशामुक्त भारत के लिए रायपुर और बिलासपुर में आयोजित 'नमो युवा रन' में युवाओं ने जोश और उत्साह से भागीदारी की। युवाओं को फिट और नशामुक्त रखने देश के 75 शहरों में यह दौड़ आयोजित की गई। राजधानी रायपुर में तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई यह दौड़ सुभाष स्टेडियम में समाप्त हुई। वहीं बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान से प्रारंभ कर रीवर-व्यू रोड में इसका समापन किया गया।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब में झंडा लहराकर 'नमो युवा रन' को प्रारंभ किया। प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर इसकी प्रतीकात्मक शुरूआत की। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, विधायकगण सर्वश्री मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव भी इस दौरान उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 'नमो युवा रन' का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश का हर युवा स्वस्थ हो, समर्थ हो, सक्षम हो और नशे से दूर रहे, इसकी जागरूकता के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं और खेलों की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार युवा शक्ति को तैयार करने का काम कर रही है।

श्री साव ने कहा कि हम हर युवा को फिट रहने के लिए खेल के मैदान से जोड़ना चाहते हैं। वे खेलों से जुड़ेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। देश को समृद्ध बनाने के लिए युवा स्वस्थ रहें तथा उत्साह व आत्मविश्वास से भरे रहें, यह जरूरी है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से स्वस्थ और नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्प लेने की अपील की।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत

कुमार ने कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वस्थ और नशामुक्त भारत के निर्माण के उद्देश्य से 'नमो युवा रन' का आयोजन किया गया है। रायपुर और बिलासपुर में आयोजित इस दौड़ में भाग लेने के लिए 20 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा उच्च शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है।

रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, नगर निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनूजा सलाम, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ एथलेटिक संघ के श्री जी.एस. बाम्बरा और केनोइंग-कयाकिंग एसोसिएशन के श्री प्रशांत रघुवंशी सहित अनेक खेल संघों के पदाधिकारी, खिलाड़ी एवं कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में 'नमो युवा रन' के शुभारंभ और समापन के मौके पर मौजूद थे।

अर्जुन राय और वंशिका पटेल को मिला प्रथम स्थान

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और अन्य अतिथियों ने सुभाष स्टेडियम में आयोजित 'नमो युवा रन' के समापन कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। पुरूष वर्ग में अर्जुन राय को प्रथम, अक्षय कुमार को द्वीतिय और चंद्रप्रकाश को तृतीय स्थान मिला। वहीं महिला वर्ग में वंशिका पटेल प्रथम, रूख्मणि साहू द्वीतीय और चंचल यादव तृतीय स्थान पर रहीं। दोनों वर्गों में प्रथम, द्वीतीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 25 हजार रुपए, 15 हजार रुपए और दस हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। वहीं चतुर्थ और पंचम स्थान हासिल करने वालों को पांच-पांच हजार रुपए तथा छटवें से दसवें स्थान पर रहने वालों को दो-दो हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों का हुआ सम्मान

उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर 'नमो युवा रन' के सुभाष स्टेडियम में समापन के दौरान अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बस्तर ओलंपिक के आइकॉन खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों के साथ प्रथम पंक्ति में बैठकर मंच साझा किया। श्री साव ने खुद आग्रहपूर्वक सभी खिलाड़ियों को मंच पर अग्रिम पंक्ति में जगह दी और उनके साथ विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय वेट-लिफ्टर श्री रूस्तम सारंग, हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे, फुटबॉलर सुश्री किरण पिस्दा और वॉलीबाल खिलाड़ी श्री दीपेश सिन्हा सहित अन्य खिलाड़ियों हितेश निर्मलकर, प्रवीण कुमार, पलक नाग, राकेश कुमार, मानो ध्रुव, पंडुराम, मानबती बघेल, मनीष मौर्य, अमृत, चुम्मन सिंह, रूपाली साहू, सुनील मोडियाम, सरिता बघेल, अनिरूद्ध, भुनेश्वरी निषाद और दामिनी सिंह को सम्मानित किया गया।

सहकार से समृद्धि और बुनकरों के उत्थान हेतु हुआ राष्ट्रीय ऐतिहासिक आयोजन

सहकार भारती बुनकर प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अधिवेशन में 13 प्रस्ताव पारित

सहकार भारती बुनकर प्रकोष्ठ का दो दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन दि 23 एवं 24 अगस्त 2025 को श्री जैनम् मानस भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ में भव्य रूप से संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र में माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, वाणिज्य मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय जी, अपेक्स बैंक अध्यक्ष के श्री केदार गुप्ता जी, सहकार भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी जी तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री दीपक चौरसिया जी ने सामूहिक दीप प्रज्वलन कर अधिवेशन का शुभारंभ किया।

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने सहकार से समृद्धि और बुनकरों के उत्थान हेतु सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा मुख्यमंत्री जी का शुभकामना संदेश साझा किया गया। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जी ने सहकार भारती के प्रयासों की सराहना की और सरकार द्वारा किए जा रहे सहकारी प्रयासों पर प्रकाश डाला। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न प्रदेशों से आए बुनकरों द्वारा लगाए गए स्टॉल का उद्घाटन भी किया गया।

विशेषज्ञ सत्रों में सहकारिता विभाग के मंत्री जी के ओएसडी श्री के. एन. कांडे जी, इफको के महाप्रबंधक श्री संतोष शुक्ला जी, नेशनल हैंडलूम प्रबंधक डॉ. आशीष जी एवं यूपीका चेयरमैन श्री अमरेश कुशवाहा जी ने अपने अनुभव व मार्गदर्शन साझा किया। देशभर से आए सफल बुनकरों में बनारस की डॉ. अंगिका कुशवाहा तथा आंध्रप्रदेश के श्रीनिवासन ने अपनी सफलता की गाथा प्रस्तुत की। रात्रि को सांस्कृतिक सत्र में प्रसिद्ध लोकगायिका श्रीमती अल्का चंद्राकर एवं असम से आयी बुनकर बहनों ने सांस्कृतिक लोककला की आकर्षक प्रस्तुति दी।

द्वितीय दिवस पर एनसीडीसी अधिकारियों ने बुनकरों

हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके पश्चात राष्ट्रीय महामंत्री श्री दीपक चौरसिया जी ने उपस्थित प्रतिनिधियों की सहमति से 'चार्टर ऑफ़ डिमांड' प्रस्तुत किया। आरबीआई निदेशक एवं सहकार भारती के संस्थापक सदस्य श्री सतीश मराठे जी ने बुनकरों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने हथकरघा की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की और इसके संरक्षण व संवर्धन पर बल दिया। समापन सत्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संजय पाचपोर जी ने बुनकरों के गौरवशाली इतिहास व स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की चर्चा करते हुए 'बुनकरों को स्वाभिमान के साथ गाँव की ओर चलने' का आह्वान किया। माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी ने बुनकरों के अनुभव साझा करते हुए 'भरोसा और ईमानदारी से सहकारिता के विकास' का मंत्र दिया तथा बाजार प्रबंधन के उपयोगी गुर भी बताए।

यह अधिवेशन सहकार भारती बुनकर प्रकोष्ठ के लिए ऐतिहासिक रहा, जिसमें देशभर से आए बुनकरों ने अपने अनुभव साझा किए, समस्याओं पर चर्चा की और आगे की दिशा तय की।

रायपुर से राजिम जाना हुआ आसान

शुरू हुई रेलगाड़ी..

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजिम में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की आवागमन सुविधा में वृद्धि करते हुए राजिम से रायपुर के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने राजिम–रायपुर–राजिम मेमू नई ट्रेन सेवा तथा रायपुर–अभनपुर 2 मेमू रेल सेवा का राजिम तक विस्तार भी प्रारंभ किया। भारी संख्या में यात्री इस अवसर पर ट्रेन में सवार हुए और उत्साहपूर्वक रायपुर की ओर रवाना हुए। सस्ती एवं सुलभ नई रेल सुविधा मिलने से पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस नई रेल सेवा से राजिम सहित गरियाबंद एवं देवभोग क्षेत्र के लोगों को भी राजधानी रायपुर तक सस्ती और किफायती यात्रा का विकल्प प्राप्त होगा। विद्यार्थी, नौकरीपेशा वर्ग और व्यापारी वर्ग सहित सभी के लिए यह ट्रेन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग, राजिम अब रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। ग्रामीण अंचलों से राजधानी रायपुर का आवागमन अब और अधिक सुगम, सुविधाजनक और किफायती बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार 19 महीनों से विकास की गति निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से हो रहा निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए नया भविष्य गढ़ेगा। उन्होंने बताया कि लगभग आठ वर्ष पूर्व धमतरी से रायपुर तक नैरोगेज ट्रेन चलती थी और अब आठ वर्षों के अंतराल के बाद यहां ब्रॉडगेज ट्रेन सुविधा उपलब्ध हुई है। इसके लिए उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़

में रेलवे की लगभग 45,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में लगभग 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश में रेल सेवाओं का तीव्र विस्तार और विकास सुनिश्चित हो रहा है।

इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, लोकसभा सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, अभनपुर विधायक श्री इन्द्रकुमार साहू, राजिम विधायक श्री रोहित साहू, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू, नगर पालिका गोबरा नवापारा अध्यक्ष श्रीमती ओमकुमारी संजय साहू, नगर पंचायत राजिम अध्यक्ष श्री महेश यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश, रेलवे अधिकारी-कर्मचारी एवं भारी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इस नई सेवा से छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम तक सीधी रेल पहुँच सुनिश्चित हो गई है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 22 मई को 'निर्मल भारत रेलवे स्टेशन' के नाम से देश के 103 रेलवे स्टेशनों को मॉडिफाई करने के लिए चयनित किया गया, जिनमें से छत्तीसगढ़ के पाँच रेलवे स्टेशन शामिल हैं और 32 स्टेशन भी इस योजना में जोड़े गए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 45,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएँ चालू हैं, जिनसे रेल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। बस्तर को भी इससे लाभ हो रहा है और रावघाट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है।

रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में बाहर से साधु-संत एवं पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। अब उन्हें सीधे रायपुर से राजिम आने की सुविधा मिलेगी, जिससे पर्यटन एवं क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और विश्व पटल पर राजिम का नाम और अधिक रोशन होगा।

महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने नई रेल सेवा के लिए लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अब राजिम से रायपुर आना बहुत आसान हो गया है। श्रद्धालु एवं पर्यटक यात्री अब राजिम से सीधे डोंगरगढ़ तक भी यात्रा कर सकेंगे।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर-अभनपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन अब राजिम तक किया जाएगा। 19 सितम्बर 2025 से नियमित समय-सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 68766/68767 राजिम-अभनपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर प्रतिदिन दोनों छोरों—राजिम और रायपुर—से संचालित होगी। इस ट्रेन में 06 सामान्य श्रेणी के डिब्बे तथा 02 पावरकार सहित कुल 08 कोच होंगे।

केन्द्र सरकार की अभिनव पहल
'प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना'

- चांटीडीह निवासी अशोक साहू ने दो घरों में लगवाया सोलर पैनल, बिजली बिल हुआ शून्य
- केन्द्र और राज्य सरकार से योजना के तहत मिल रही सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से घरों तक रोशनी पहुंचाई जा रही है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हितग्राहियों को केन्द्र सरकार की ओर से 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार तक की सब्सिडी दी जा रही है साथ ही प्रतिमाह 300 यूनिट फ्री बिजली का भी प्रावधान है। योजना के तहत बिलासपुर जिला चांटीडीह निवासी श्री अशोक साहू ने अपने दो घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया है, उन्होंने चार किलोवाट और तीन किलोवाट के दो सोलर पैनल लगवाएं हैं जिनमें से एक उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति साहू के नाम है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से राहत मिल रही है और उनके दोनों घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

चांटीडीह निवासी श्री अशोक साहू ने बताया कि उनके दो घर हैं एक उनकी पत्नी के नाम और एक स्वयं उनके नाम पर, घर बड़ा और संयुक्त परिवार होने के कारण बिजली की खपत काफी अधिक थी जिससे बिल काफी

अधिक आता था। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के विषय में जानकारी मिलने पर उन्होंने भी इसे लगवाने का निर्णय लिया और दोनों घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट की लागत 190000 थी जो 90 प्रतिशत उनकी पत्नी के नाम पर फाइनेंस हो गया। वहीं चार किलोवाट की लागत 240000 थी जिसमें से केंद्र द्वारा सब्सिडी के रूप में 78000 और राज्य सरकार की सब्सिडी 30000 रुपए उनके खाते में आ गए हैं। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर लगे सोलर पैनल की सब्सिडी भी जमा हो गई है। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने अपने दोनों घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया है, उनके बिजली बिल शून्य हो गया है। सोलर पैनल के जरिए छत पर हो रहे बिजली उत्पादन से उनकी प्रतिमाह बिजली पर होने वाले खर्च की बचत हो रही है। श्री साहू ने बताया कि दोनों घरों की छत पर 7 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे हो रहे बिजली उत्पादन से प्रतिमाह बिजली बिल की अब चिंता नहीं रही, वहीं वे उत्पादक के रूप में भी बिजली की सप्लाई भी कर रहे हैं जो गर्व की बात है। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केवल 1 बार निवेश करना है जिसके बाद 25 वर्षो तक बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। लंबे समय के लिए यह एक बेहद किफायती योजना है जिसके लिए बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने बताया कि एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद इस पर किसी प्रकार का मेंटेनेन्स खर्च नहीं है और पैनल लगाने वाली कंपनी द्वारा 5 साल तक नि:शुल्क सविर्सिंग की सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। इस माध्यम से हम सौर ऊर्जा कर उपयोग कर बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, जो ग्रीन एंनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस योजना को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें।

उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से कम बिजली बिल, बिजली उत्पादन कर आत्मनिर्भरत और नवीन रोजगार का भी सृजन हो रहा है। इससे नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। शासन द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकते हैं।

श्रमिकों के जीवन में आई खुशहाली...

श्रमिकों के उत्थान के लिए 535.62 करोड़ रूपए की राशि दिया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए लगातार उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीयन एवं लाभांवित श्रम विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 तक लगभग 7.3 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है तथा वर्ष 2024 से 15 सितम्बर 2025 तक संचालित योजनाओं के माध्यम से लगभग 8.39 लाख श्रमिकों को लाभांवित हुए हैं, जिस पर लगभग 535.62 करोड़ रूपए व्यय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में एक नई पहल शुरू की गई है। असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवारों के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना 'अटल श्रम सशक्तिकरण योजना' प्रारंभ की गई है। प्रवासी श्रमिक साथियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदाय करने हेतु प्रथम चरण में 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में जहां अधिक संख्या में श्रमिक प्रवास करते हैं, वहां 'मोर चिन्हारी भवन' बनाया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है। इससे उन्हें हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि के लिए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में उपचार सुविधा मिलेगी।

इसी तरह राज्य शासन द्वारा श्रम विभाग की 'अम्ब्रेला योजना अटल श्रम सशक्तिकरण योजना' के नाम से शुरू की गई है। इससे श्रमिकों तथा उनके परिवारों को एक ही स्थान पर सरकार के सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके लिए 'श्रमेव जयते' पोर्टल बनाया गया है। पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने के लिए जल्द ही नई योजना शुरू की जा रही है ताकि आत्म

निर्भर बनते हुए स्वयं मालिक बनने की दिशा में बढ़ सकें। इसके अलावा असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सतत् निगरानी हेतु राज्य के प्रत्येक संभाग में संभाग स्तरीय श्रम कल्याण कार्यालय के स्थापना की जा रही है।

श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण एवं सहायता हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय तथा समस्त विकासखंडों में मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना अंतर्गत 01 जनवरी, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 तक 94,300 निर्माण श्रमिकों को पंजीयन/नवीनीकरण/योजनाओं के आवेदन में सहयोग प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु स्व-घोषणा प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल करते हुये, ठेकेदार अथवा नियोजक के अधीन कार्य करने संबंधी नियोजक से नियोजन प्रमाण पत्र के स्थान पर श्रमिकों से ही निर्माण कार्य में नियोजित होने संबंधी स्वघोषणा पत्र का प्रावधान किया गया है। उक्त सरलीकरण करने से श्रमिकों को पंजीयन कराने में सुविधा हुई है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के स्वयं के आवास क्रय एवं आवास निर्माण हेतु 01 लाख रूपये एकमुश्त अनुदान सहायता राशि प्रदाय किया जा रहा है। 01 जनवरी, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 तक 1042 निर्माण श्रमिकों को नवीन आवास क्रय/आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि प्रदाय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित उक्त योजनांतर्गत कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं छत्तीसगढ़ बोर्ड के मेरिट के प्रथम 10 में स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक श्रमिक बच्चों को राशि रूपये 01 लाख प्रोत्साहन राशि तथा रूपये 01 लाख दोपहिया वाहन क्रय करने हेतु प्रदाय किया गया है। 01 जनवरी, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 तक निर्माण श्रमिक के 7478 पुत्र/पुत्रियों को 10 करोड़ 14 लाख 49 हजार 614 रूपए प्रदान किया गया है।

प्रसूति सहायता योजना 01 जनवरी, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 तक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित 'मिनीमाता महतारी जतन योजना' अंतर्गत 65 हजार 010 महिला निर्माण श्रमिकों को लाभांवित किया गया है।शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना उक्त योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण, असंगठित एवं संगठित श्रमिकों को 05 रूपए में गरम एवं पौष्टिक भोजन प्रदाय किया जा रहा है। 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में 29 भोजन केन्द्र संचालित थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर 17 जिलों में 37 भोजन केन्द्र हो गये हैं। 01 जनवरी, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 विभाग द्वारा 11,35,362 यूनिट भोजन (मिल) पंजीकृत संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को प्रदाय किया जा चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा राशि रूपये रूपये 52,865,395 व्यय हुआ है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सामान्य मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक लाख रूपए की राशि, कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपए की राशि तथा कार्य स्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर श्रमिक को ढ़ाई लाख रूपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। जिसके तहत् 01 जनवरी, 2024 से 15 सितम्बर, 2025 तक कुल 3658 निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को लाभांवित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 सितंबर 2024 को डी.बी.टी. के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया था। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित कर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को केन्द्रीकृत डी.बी.टी. के माध्यम से लाभांवित करना प्रारंभ कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 17 सितम्बर, 2024 से अब तक 16 योजनाओं में 6 लाख 48 हजार 633 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 327 करोड़ 13 लाख 53 हजार 108 रूपए से लाभांवित किया गया।

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे ग्रीन कॉरिडोर...

'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के तहत सड़कों के किनारे और डिवाइडर्स पर पौधरोपण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जहां एक ओर देश में सड़कों का जाल बिछा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजमार्गों के किनारों और डिवाइडर्स पर पौधे लगाकर ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के तहत इस साल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और डिवाइडर्स पर दो लाख 71 हजार से ज्यादा पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ-साथ प्राधिकरण उन्हें 'ग्रीन कॉरिडोर' में भी बदल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान छत्तीसगढ़ में हरियाली, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो लाख 71 हजार से अधिक पौधे रोपित होना इस बात का प्रमाण है कि सड़क निर्माण केवल विकास की आधारशिला नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु और हरित जीवन का भी संकल्प है। राष्ट्रीय राजमार्ग से छत्तीसगढ़ में नागरिकों को तरक्की की राह के साथ ही हरियाली की छांव भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर का यह प्रयास छत्तीसगढ़ को न केवल यातायात सुविधा में बल्कि पर्यावरणीय संतुलन में भी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।

उल्लखेनीय है कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के अंतर्गत इस साल निर्धारित लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण किया है। रायपुर-विशाखापट्टनम (NH-130CD) परियोजना में सर्वाधिक 97 हजार 145 पौधे लगाए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सीमा-दुर्ग-रायपुर-ओडिशा सीमा (NH-53) पर 46 हजार 141 पौधे, चांपा-कोरबा-कटघोरा (NH-149B) मार्ग पर 23 हजार 020 पौधे, बिलासपुर-कटघोरा (NH-130) मार्ग पर 16 हजार 847

पौधे, बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव (NH-130A) मार्ग पर 14 हजार 400 पौधे तथा सिमगा-रायपुर-धमतरी (NH-30) परियोजना में 5406 पौधे रोपे गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के डिवाइडर्स पर मीडियन प्लांटेशन के रूप में पौधे लगाए गए हैं, जबकि किनारों पर एवेन्यू प्लांटेशन के रूप में पौधरोपण किया गया है। इनमें काफी संख्या में बड़े फलदार और छायादार वृक्ष भी शामिल हैं। नए इलाकों में पौधरोपण के साथ ही पिछले वर्षों में क्षतिग्रस्त हुए पौधों को बदलने के लिए 68 हजार 297 जगहों पर रिप्लांटेशन भी किया गया है। इस तरह चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक (15 सितम्बर 2025 तक) कुल दो लाख 71 हजार 253 पौधे राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी (Regional Officer) श्री प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' सिर्फ एक वृक्षारोपण अभियान नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ी के लिए एक निवेश है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सड़कों का निर्माण करना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सुन्दर पर्यावरण का भी निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों में इस साल दो लाख दो हजार 959 नए पौधे लगाए गए हैं, जबकि 68 हजार 297 जगहों पर रिप्लांटेशन किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस साल (2025-26 में) अब तक कुल दो लाख 71 हजार 253 पौधे लगाए जा चुके हैं।

श्रीरामलला दर्शन योजना

गरीबों के आयोध्या दर्शन का सपना कर रहा पूरा...

श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर इस विशेष ट्रेन को जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुंगेली जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्रीकांत पांडे, बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, पूर्व महापौर श्रीमती वाणी राव और नगर निगम के सभापति श्री विनोद सोनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा रेलवे के कर्मचारी उपस्थित थे।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे-बाजे और पारंपरिक नृत्य के साथ तिलक लगाकर भक्तों का स्वागत किया गया। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए जा रहे इन श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा।

जल जीवन मिशन ने बदली जिंदगी

पहले अधिकांश समय पानी के इंतजाम में ही निकल जाता था, पर अब घर पहुंच रहा पानी

हर घर नल से पानी पहुंचाने के मिशन 'जल जीवन मिशन' ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। पहले सुबह का अधिकांश समय परिवार के लिए पानी के इंतजाम में बिताने वाली महिलाएं अब घर में नल से पानी आने के बाद राहत की सांस ले रही हैं। अब उन्हें बच्चों की परवरिश, पढ़ाई-लिखाई, खेती, मजदूरी और आजीविका के अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिल जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के बिंजाम ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के माध्यम से 267 घरों में नल से जल पहुंचाया है। इससे गांववाले और वहां की महिलाएं काफी खुश हैं। गांव को ''हर घर जल ग्राम'' का दर्जा भी मिल गया है।

बिंजाम के अधिकांश परिवार आजीविका के लिए खेती और मजदूरी पर आश्रित हैं। यहां पहले पेयजल का मुख्य स्रोत हैंडपंप ही था। पर अब जल जीवन मिशन से गांव के हर घर में नल से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। जल आपूर्ति के लिए गांव में 16 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई गई है। तीन उच्च स्तरीय जलागारों (पानी टंकियों) के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

जल जीवन मिशन से हर परिवार को न केवल पर्याप्त जल मिल रहा है, बल्कि यह स्वच्छ और सुरक्षित भी है। गांव में गठित 'जल वाहिनी' समूह की महिलाओं को जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये महिलाएं फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल की गुणवत्ता का परीक्षण कर गांव में गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। इससे गांववाले अब जलजनित और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के खतरे से मुक्त हो गए हैं।

जल जीवन मिशन ने बिंजाम की महिलाओं का जीवन बदल दिया है। पहले धूप, गर्मी, बरसात, ठंड या रात होने पर भी महिलाओं को पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता था। घर पर छोटे बच्चे हों या खुद की तबीयत खराब हो, तो भी पानी लेने बाहर निकलना ही पड़ता था। पर अब

घर में ही नल लग जाने से हालात बदल गए हैं। रोज की परेशानियों से निजात मिल गई है।

बिंजाम की महिलाएं बताती हैं कि पहले घर के सभी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था में बहुत समय लगता था, मेहनत भी बहुत लगती थी। सुबह का ज्यादातर समय इसी में निकल जाता था जिसके चलते उनकी दुनिया सिमट सी गई थी। परिवार के खेती-किसानी के कार्यों में न वे ठीक से सहयोग कर पाती थीं और न ही अन्य कोई रोजगारमूलक गतिविधियों के बारे में सोच सकती थीं। पर अब जल जीवन मिशन ने ये सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। अब बच्चे रोज समय पर बिना रूकावट के स्कूल जा रहे हैं। महिलाएं को अब अपनी सब्जी-बाड़ी और वनोपज संग्रहण के साथ ही खेत और घर के अन्य कामों के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है।

आदि कर्मयोगी लाएंगे जनजातीय गांवों में जमीनी बदलाव : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित सड्डू के प्रयास आवासीय विद्यालय में आदि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय गांवों के जमीनी बदलाव की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके शतायु एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनजातीय गांवों का ट्राइबल विजन डाक्यूमेंट 2030 तैयार किया जाएगा, जो दीर्घकालीन विकास का रोडमैप बनेगा। आगामी 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभाओं में इसका अनुमोदन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के धार से इस अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य जनजातीय गांवों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। इसके तहत ऐसे वालंटियर चिन्हांकित किए जाएंगे जो गांव की बेहतरी के लिए विजन रखते हों और उसे जमीनी स्तर पर लागू कर सकें। देशभर में 20 लाख वालंटियर तैयार करने का लक्ष्य है, जिनमें से छत्तीसगढ़ के 6,650 गांवों में 1 लाख 33 हजार वालंटियर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने आदि सेवा केंद्रों की स्थापना भी की है, जहां ग्रामीण शासन की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और अपनी

शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे देश की जनजातीय विरासत गौरवशाली रही है। राज्य सरकार शहीद वीरनारायण सिंह और गुंडाधुर जैसे जनजातीय नायकों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही है। नवा रायपुर में जनजातीय नायकों की स्मृतियों को सहेजने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ट्राइबल म्यूजियम में छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जनजातीय गांवों के लिए पीएम जनमन योजना तथा धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के अंतर्गत दिए गए बजट के अनुरूप तेजी से कार्य हो रहा है। जिन क्षेत्रों तक विकास की गति अभी पूर्ण रूप से नहीं पहुँची है, वहाँ अब आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से प्रत्येक घर तक विकास पहुँचाया जाएगा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम है। इसके माध्यम से देश के 11 करोड़ से अधिक आदिवासियों के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में लोकप्रिय नेता और नए भारत के निर्माता प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयास से ही 2047 तक विकसित भारत का संकल्प अवश्य पूरा होगा। हमारी सरकार सेवा, समर्पण और मिशन मोड पर आदि कर्मयोगी अभियान को आगे बढ़ा रही है। रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं और आदि कर्मयोगी अभियान से जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणी बोरा ने विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश के 6,650 गांवों में 1 लाख 33 हजार आदि साथी व आदि सहयोगी तैयार किए जा रहे हैं। ये सहयोगी आदिवासी परिवारों से उनकी भाषा में संवाद कर उनकी समस्याओं व अपेक्षाओं को समझेंगे और विकास की दिशा तय करने में सहभागी बनेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी राज्योत्सव तक 50 हजार आदि कर्मयोगी तैयार करने का लक्ष्य है। साथ ही, शिष्यवृत्ति प्रदाय की समय-सीमा तय कर दी गई है ताकि विद्यार्थियों को राशि समय पर उनके खातों में प्राप्त हो सके।

शिष्यवृत्ति और भोजन सहायता के तहत 6.2 करोड़ की राशि अंतरित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आदि सेवा पखवाड़ा के शुभारंभ अवसर पर आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग विभाग की योजनाओं के तहत प्रदेश के आश्रम-छात्रावासों में निवासरत 8,370 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं भोजन सहायता योजना की राशि 6 करोड़ 2 लाख 19 हजार 270 रुपये का ऑनलाइन अंतरण उनके खातों में किया।

एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत पौधरोपण

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रयास आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 के अंतर्गत जामुन का पौधा रोपा। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने पेंटिंग व रंगोली प्रदर्शित की, जिनका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और बच्चों की रचनात्मकता की सराहना की। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को उनके चित्र की पेंटिंग भेंट की।

मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के साथ किया भोजन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के छात्र किशन बैगा और छात्रा अंजुला बैगा को अपने बगल में बैठाकर विद्यार्थियों के साथ भोजन किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ मुनगा की सब्जी, पूड़ी और दाल-भात का स्वाद लेते हुए उनसे आत्मीय बातचीत की। किशन ने बताया कि वह मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लाखनटोला गांव का निवासी है और प्रयास विद्यालय सड्डू में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत है। मुख्यमंत्री ने उससे गांव में प्रधानमंत्री जनमन योजना के कार्यों के बारे में पूछा। कक्षा 12वीं की छात्रा अंजुला ने बताया कि वह देवगढ़ गांव (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) की रहने वाली है और जीव विज्ञान विषय लेकर पढ़ाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोनों को मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया।

महतारियों के सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ सरकार ने कायम की मिसाल

[डॉ. दानेश्वरी संभाकर]

स्त्री पुरुष समानता के मामले में छत्तीसगढ़ की मिसाल पूरे देश में रही है लेकिन आर्थिक समानता में फिर भी पुरुषों का पलड़ा अब तक भारी होता था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सरकार आने के बाद इस आर्थिक विषमता को दूर करने का रास्ता भी खुल गया है। अब छत्तीसगढ़ की हर माँ और बहन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए वे स्वयं निर्णय ले सकती हैं। महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को उनके श्रम और भागीदारी के लिए सम्मानित करती हैं वहीं साय सरकार की आजीविकामूलक योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की राह मिली है। आधी आबादी को सशक्त कर मुख्यमंत्री ने विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला रख दी है।

छत्तीसगढ़ ने पिछले 19 महीनों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और त्वरित लाभ पहुंचाने की व्यवस्था स्थापित की गई है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।

आर्थिक स्वावलंबन - महतारी वंदन योजना आत्मनिर्भर महिला की ओर कदम

1 मार्च 2024 से लागू इस महत्वाकांक्षी योजना ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में क्रांति ला दी है। विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जा रहे हैं।मार्च 2024 से

सितम्बर 2025 तक 69.15 लाख से अधिक महिलाओं को 12,376.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।यह राशि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, पोषण और मूलभूत जरूरतों की पूर्ति में सहायक है।चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 5, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 179 महतारी सदन के निर्माण के लिए 52.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक सदन 2,500 वर्गफुट में 29.20 लाख रुपए की लागत से बनेगा, जो महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, बैठक और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र होगा।

स्वरोजगार और उद्यमिता का विस्तार

साय सरकार ने महिला श्रमिकों और स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं -

जिसमें मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को 7,900 रुपए की सहायता एक सिलाई मशीन के लिए दी जा रही है।दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना से 3 वर्ष से पंजीकृत महिला श्रमिकों को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिला श्रमिकों को 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना ने पंजीकृत श्रमिकों को अपनी 18-21 वर्ष की अविवाहित पुत्रियों के पढ़ाई लिखाई तथा अन्य आवश्यक खर्चों के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी साय सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें महतारी शक्ति ऋण योजना के माध्यम से उन्हें बिना जमानत के 25,000 रुपए का ऋण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।सक्षम योजना - 2 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को 3% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक ऋण भी दिया जा रहा है।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - 800 करोड़ रुपए का प्रावधान, 'लखपति महिला' और 'ड्रोन दीदी' जैसी नवाचारी पहलें भी योजनाओं में शामिल है।इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ, उन्हें रोजगार के स्थायी अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। साय सरकार ने महिला सुरक्षा को नीति के केंद्र में रखा है।

नवाबिहान योजना से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा, परामर्श और आश्रय सुविधा प्रदान की जाती है।इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ सखी वन-स्टॉप सेंटर में SOP लागू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। 27 जिलों में सेंटर संचालित, 24×7 सेवा उपलब्ध है। महिला हेल्पलाइन 181 और डायल 112 द्वारा संकट में फंसी महिलाओं को त्वरित सहायता और पुलिस समन्वय की सुविधा प्रदान की जाती है।

शुचिता योजना के तहत 2,000 स्कूलों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें, 3 लाख से अधिक किशोरियों को स्वच्छता सामग्री प्रदान की जा रही है जिसके लिए 13 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है।हाई स्कूल छात्राओं के लिए साइकिल वितरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य पूरक और पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है,जहाँ महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री होगी।जशप्योर ब्रांड जशपुर जिला में निवासरत आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित वन-आधारित उत्पाद है,जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान बना रहा है, साथ ही 'वोकल फॉर लोकल' का सफल उदाहरण भी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग को 8,245 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है। इसमें महतारी वंदन, पोषण, स्वास्थ्य, ऋण और सुरक्षा योजनाओं का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का मानना है कि महिला सशक्तिकरण केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि धरातल पर वास्तविक बदलाव लाने से संभव है। वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुँचे।

हिन्दी दिवस : हिन्दी की सरलता और व्यापक स्वीकार्य

शासन की योजनाओं और सेवाओं को सरलता से पहुँचाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही

भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा आधार उसकी भाषाई संस्कृति है। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं, किन्तु हिन्दी ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने का कार्य किया है। 14 सितम्बर, हिन्दी दिवस के अवसर पर हमें यह स्मरण करना आवश्यक है कि हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।

धमतरी जिले सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में जनमानस प्राय: क्षेत्रीय बोलियों जैसे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी आदि के माध्यम से संवाद करता है। किंतु जब शासकीय कार्य, शैक्षणिक क्षेत्र अथवा व्यापक सामाजिक संपर्क की बात आती है, तो हिन्दी सबको जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है। यही कारण है कि राज्य शासन और जिला प्रशासन का अधिकांश कामकाज हिन्दी भाषा में ही संपन्न होता है। हिन्दी की यह प्रशासनिक भूमिका जनसाधारण तक शासन की योजनाओं और सेवाओं को सरलता से पहुँचाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है।

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएँ बस्तर से लेकर सरगुजा तक विस्तृत हैं, और इन क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ व बोलियाँ प्रचलन में हैं। ऐसे विविध वातावरण में हिन्दी संवाद का सेतु बनकर कार्य करती है। यही नहीं, हिन्दी के माध्यम से राज्य की संस्कृति, साहित्य और सामाजिक जीवन को भी व्यापक मंच प्राप्त होता है। जन-जन तक पहुँचने की क्षमता के कारण हिन्दी ने प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को भी सुदृढ़ किया है।

हिन्दी की महानता उसकी सरलता, सहजता और व्यापक स्वीकार्यता में निहित है। यह भाषा न केवल भारत के विभिन्न राज्यों को जोड़ती है, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को भी अपनी मातृभूमि से आत्मीयता का

अनुभव कराती है। वैश्विक स्तर पर भी हिन्दी का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीक, व्यापार और संचार के क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग व्यापक हो रहा है, जो इसे आधुनिक युग में और अधिक प्रासंगिक बना रहा है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हिन्दी के गौरव को केवल उत्सव तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जीवनचर्या में व्यवहारगत रूप से अपनाएँ। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को हिन्दी लेखन, वाचन और अभिव्यक्ति के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध कराना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र में भी हिन्दी के प्रयोग को और सशक्त करना आवश्यक है।

हिन्दी दिवस केवल एक स्मरण मात्र नहीं है, यह हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। धमतरी जिले के नागरिकों की हिन्दी के प्रति आत्मीयता और गर्व इस बात का प्रमाण है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, समाज और राष्ट्र की आत्मा होती है।

मालूम हो कि संविधान सभा ने लिया था ऐतिहासिक फैसला भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था – राष्ट्रभाषा का। एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। हिंदी, जिसे एक विशाल जनसंख्या द्वारा बोला और समझा जाता था, इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार थी।

इसी कड़ी में, 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस दिन, संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 के तहत यह तय किया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। इस फैसले ने हिंदी को देश की पहचान और प्रशासनिक कार्यों का केंद्र बिंदु बना दिया।

'इसी फैसले के कारण देश में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से लेकर आज तक यह सिलसिला जारी है।

कहा जा सकता है कि हिन्दी हमारी पहचान, हमारी धरोहर और हमारी एकता की सबसे मजबूत डोर है। इसके माध्यम से ही हम भारतीयता के उस मूल भाव को जीवित रख सकते हैं, जो हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गर्व प्रदान करता है। हिन्दी दिवस पर यही संकल्प होना चाहिए कि हम हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसके सम्मान को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

गेंदा फूल की खुशबू से महक रहा महिलाओं का जीवन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत महिलाओं के स्व-सहायता समूह गेंदा फूल की खेती कर आजीविका संवर्धन की दिशा में नई मिसाल गढ़ रहे हैं। कांकेर जिले के महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी राशि से समूहों की महिलाओं ने गेंदा फूल की खेती प्रारंभ की है।

उन्नत खेती की दिशा में उद्यानिकी विभाग के सहयोग से माह मई-जून में 50 से 55 महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण उपरांत कांकेर विकासखंड के विभिन्न ग्रामों-पीढ़ापाल से रामरहीम समूह, भीरावाही से जय अंबे समूह, कोकपुर से मां दंतेश्वरी समूह, मुरडोंगरी से पूजा समूह, किरगोली से सरस्वती समूह तथा बारदेवरी से जय अंबे समूह ने 10 से 20 डिसमिल क्षेत्र में गेंदा फूल की खेती प्रारंभ की। इस प्रकार कुल एक एकड़ भूमि में 17,600 पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही 50 डिसमिल में अतिरिक्त 2,700 पौधे भी लगाए गए हैं।

मुरडोगरी की पूजा स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती जगबती ने बताया कि 20 से 30 डिसमिल क्षेत्र में की गई खेती से अब तक 69 किलो फूल की उपज प्राप्त हुई है। इसे 60 से 70 रुपए प्रति किलो की दर से विक्रय कर महिलाओं ने 4,000 से 5,000 रुपए की आय अर्जित की है। उन्होंने कहा कि इस गतिविधि से वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत महिलाओं की यह पहल ग्रामीण क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायी बन रही है। गृह कार्य के साथ-साथ रोजगार अर्जित कर महिलाएं अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। कलेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर, सीईओ जिला पंचायत श्री हरेश मंडावी ने बताया कि 18 सितम्बर से 35 महिलाओं को गेंदा फूल की उन्नत खेती का प्रशिक्षण आरसेटी में दिया जा रहा है। इससे महिलाएं आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकेंगी तथा भविष्य में अन्य जिलों में विक्रय कर अपनी आय में और वृद्धि कर पाएंगी।

ईंब नदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल...

बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी 9 करोड़ 18 लाख की लागत से होगा निर्माण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी होती जा रही है। जशपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धौरासांड से दाईजबहार मार्ग पर ईब नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है। यह निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। पुल बन जाने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षों बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही।

मिलेगी आवागमन की बड़ी सुविधा

इस उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के बाद फरसाबहार क्षेत्र के दाईजबहार, बरकशपाली, साजबहार, बामहनमारा, तपकरा से धौरासांड, खुटगांव, बनगांव, हेटघिंचा और तुबा जैसे गांवों की दूरी काफी कम हो जाएगी। ग्रामीणों को अब लंबी दूरी का आवागमन नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी।

ओडिशा और झारखंड राज्य से होगा सीधा संपर्क

ईब नदी पर बनने वाला यह उच्च स्तरीय पुल केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह मार्ग छत्तीसगढ़ को सीधे ओडिशा और झारखंड राज्यों से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग बन जाएगा, इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

फरसाबहार क्षेत्र के ग्रामीणों ने ईब नदी में पुल निर्माण की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह पुल न केवल उनके जीवन को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

एमसीबी जिले का वर्षगांठः

200 वर्षों बाद हुआ पुनः विभाजन...

छत्तीसगढ़ के 32वें जिले के रूप में 9 सितम्बर 2022 को अस्तित्व में आया मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला, जो कोरिया जिले से विभाजित होकर बना और जिसका मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में स्थापित किया गया। जिले के नोडल अधिकारी पर्यटन, पुरातत्व एवं इतिहासकार डॉ. विनोद कुमार पांडेय बताते हैं कि पूर्व में कोरिया रियासत में 1600 ई. तक राजा बालंद का शासन था। 1750 में मैनपुरी के चौहान वंश के दलथम्मन शाही व धारमलशाही कोरिया पहुंचे और वहां कोल जाति व गोंडों के बाद चौहान वंश का राज्य स्थापित हुआ। यह वंश स्वयं को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वंशज मानता है। कुछ समय उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों नागपुर के मोड़ेजी भोसले के परास्त हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकांश राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए और उसी के साथ कोरिया राज्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। 24 दिसंबर 1819 में राजा गरीब सिंह के स्वीकृत करारनामा के अनुसार राज्य को 400 रुपये वार्षिक अंग्रेजों को देने का प्रावधान किया गया, साथ ही चांगभखार रियासत (जनकपुर) कोरिया की सामंती अधीनता होने के कारण 386 रुपये कोरिया राज्य के माध्यम से कंपनी को देना तय हुआ। आगे डॉ. पांडेय बताते हैं कि राजा गरीब सिंह के बाद राजा अमोल सिंहदेव का शासन प्रारंभ हुआ। सन् 1848 में हुए एक अन्य अनुबंध के अनुसार चांगभखार रियासत ने देय राशि सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को देना शुरू कर दिया और इस प्रकार वह कोरिया रियासत से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया तथा उसे 'भैया' की उपाधि दी गई। कालांतर में इतिहास ने करवट ली और लगभग 200 वर्षों बाद 25 मई 1998 को रियासत के इसी हिस्से में कोरिया जिले का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय बैकुंठपुर बनाया गया और इसका क्षेत्रफल 5977.70 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया। जिस प्रकार 1848 में कोरिया रियासत से अलग होकर चांगभखार रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बना था, उसी प्रकार इतिहास दोहराया गया और 9 सितंबर 2022 को कोरिया जिले से अलग होकर नवीन मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय मनेंद्रगढ़ बनाया गया। इसमें पूर्व चांगभखार रियासत तथा कोरिया रियासत का कुछ भाग शामिल किया गया। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का गठन कोरिया जिले के उपखंड मनेंद्रगढ़ (तहसील मनेंद्रगढ़ व केल्हारी), उपखंड भरतपुर (तहसील भरतपुर), उपखंड खड़गवां-चिरमिरी (तहसील खड़गवां एवं चिरमिरी) को समाविष्ट करते हुए किया गया। इसकी सीमाएं उत्तर में तहसील कुसमी जिला सीधी-सिंगरौली (मध्यप्रदेश), दक्षिण में तहसील पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा एवं तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर, पूर्व में तहसील बैकुंठपुर एवं सोनहत तथा पश्चिम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही व अनूपपुर (मध्यप्रदेश) जिले से मिलती हैं। जिले का क्षेत्रफल 1726.39 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4,22,248 थी।

जिले के नामकरण के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए डॉ. पांडेय बताते हैं कि वास्तव में मनेंद्रगढ़ का मूल नाम कारीमाटी था, क्योंकि यहां के आसपास कोयले का विशाल भंडार था तथा इस भूभाग की मिट्टी काली थी। सन 1927 में कारीमाटी में भीषण आग लग गई, जिससे संपूर्ण क्षेत्र जलकर राख हो गया। 1930 में रेलवे लाइन आने के बाद तत्कालीन कोरिया राजा रामानुज प्रताप सिंह ने रेलवे स्टेशन के निकट नगर बसाने का निर्णय लिया और इस स्थान का नाम अपने तृतीय पुत्र महेंद्र प्रताप सिंहदेव के नाम पर मनेंद्रगढ़ रखा। चिरमिरी नाम की उत्पत्ति का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी एक मत के अनुसार यहां चेरी माई की स्मृति में स्थित एक सती मंदिर था, जो भग्नावस्था में था और उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम चिरमिरी पड़ा होगा। इसी प्रकार जनकपुर का संबंध चांगभखार रियासत से रहा है और इसका नामकरण रियासत की कुलदेवी माता चांगदेवी के नाम पर किया गया था।

फिजिक्स, केमेस्ट्री और संस्कृत से दूर हुआ डर

युक्तियुक्तकरण से केरवाद्वारी हायर सेकेण्डरी स्कूल में बदला पढ़ाई का माहौल

कोरबा जिले के करतला विकासखण्ड अंतर्गत वनांचल ग्राम केरवाद्वारी में स्थित हायर सेकेण्डरी विद्यालय में अब पढ़ाई का माहौल पूरी तरह बदल गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ने यहां के विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान दी है।

विद्यालय में भौतिकी एवं रसायन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के नियमित व्याख्याता न होने से विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावक भी चाहते थे कि उनके बच्चों को सभी विषयों की नियमित पढ़ाई का अवसर मिले। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत केरवाद्वारी हायर सेकेण्डरी विद्यालय में भौतिकी, रसायन एवं संस्कृत विषय के व्याख्याताओं की पदस्थापना हुई। इससे विद्यालय में न केवल पढ़ाई का माहौल सुधरा है, बल्कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों ने बताया कि अब उन्हें कठिन लगने वाले प्रश्न भी सरल ढंग से समझ में आने लगे हैं। शिक्षिकाओं द्वारा किताबों के साथ-साथ व्यावहारिक उदाहरणों से पढ़ाने की शैली ने विषयों को रोचक बना दिया है। छात्राओं ने कहा कि शिक्षिकाएँ सहज और सहयोगी वातावरण में पढ़ाती हैं, जिससे सवाल पूछने में झिझक नहीं होती।

विद्यालय के प्राचार्य श्री सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि नियमित व्याख्याताओं की पदस्थापना से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा है और आने वाले वर्षों में और अधिक विद्यार्थी विज्ञान संकाय सहित अन्य विषयों में दाखिला लेंगे। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल ने वनांचल के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया है।

'आत्मनिर्भरता से ही देश का भविष्य सुरक्षित...'

गुजरात दौरे पर PM Modi का संदेश, 34 हजार करोड़ की दी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे (PM Modi in Bhavnagar Gujarat) पर थे। इस दौरान भावनगर में उनका एक किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। हवाई अड्डे से शुरू हुआ यह रोड शो गांधी मैदान तक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने उन पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। सड़कों के दोनों ओर 'ऑपरेशन सिंदूर विजय' और 'जीएसटी सुधारों' के लिए आभार व्यक्त करने वाले पोस्टर लगे हुए थे।

पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर जोर

गांधी मैदान से आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 'समुद्र से समृद्धि' जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सामने 'विश्वबंधु' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और देश नहीं, बल्कि विदेशी निर्भरता है। उन्होंने कहा, 'जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ही हमारी असफलता होगी। हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा।'

आत्मनिर्भरता ही समाधान

पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश भारत को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने गुजराती कहावत का जिक्र करते हुए कहा, 'सौ समस्याओं की एक ही दवा है, और वह है भारत का आत्मनिर्भर बनना।'

रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। माहौल पूरी तरह चुनावी रैली जैसा था। लोगों ने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए।

मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन

अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मुंबई के इंदिरा डाक पर बने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। यह टर्मिनल समुद्री यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा।

विकास और आत्मनिर्भरता का संकल्प

पीएम मोदी का गुजरात दौरा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसमें विकास और आत्मनिर्भरता का संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा और 1.4 अरब देशवासियों का भविष्य केवल आत्मनिर्भर भारत की नींव पर टिका होगा।

वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिताओं को तत्काल लागू करें : भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मज़दूर संघ
Bharatiya Mazdoor Sangh

भारतीय मजदूर संघ की भोपाल में आयोजित 159वीं केंद्रीय कार्यसमिति (केंद्रीय कार्यकारिणी) ने केंद्र सरकार से वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता को तत्काल लागू करने की मांग की। केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में मांग की गई कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय, सर्वोच्च त्रिपक्षीय समिति, भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का जल्द से जल्द आयोजन करे।

केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक 22 से 24 अगस्त, 2025 तक भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें तीन प्रस्ताव पारित किए गए। मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या की अध्यक्षता में अ.भा. महामंत्री रवींद्र हिमते ने बैठक का संचालन किया। वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिताएँ ऐतिहासिक हैं और आम श्रमिकों के लिए लाभकारी हैं। इसलिए, भारतीय मजदूर संघ लगातार इनके तत्काल क्रियान्यवन पर जोर दे रहा है।

भारतीय मजदूर संघ औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता में श्रमिक हितों के विरुद्ध होने के कारण दोनों संहिताओं का विरोध कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ का अनुरोध है कि भारत सरकार त्रिपक्षीय सहयोगियों को विश्वास में लेकर चरणबद्ध तरीके से श्रम संहिताओं को लागू करें। चारों श्रम संहिताओं को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।

भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) सन् 2015 में आयोजित किया गया था। उसके बाद, यह आयोजित नहीं किया गया। आईएलसी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत सर्वोच्च त्रिपक्षीय समिति है। 2015 के बाद, श्रम जगत के कई आयामों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। प्रौद्योगिकी, डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल परिवर्तन ने सामाजिक जीवन और आर्थिक परिदृश्य में कई बदलाव लाए हैं। इस सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में श्रम मुद्दों पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता है।

केंद्रीय कार्यसमिति ने कौशल विकास योजना के तहत ठेका श्रमिकों को नियमित करने हेतु हरियाणा सरकार के निर्णय का स्वागत किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय कार्यसमिति ने आईसीडीएस योजना के तहत महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई फैस रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) को लेकर अपनी आशंकाएँ व्यक्त की थीं। क्रियान्वयन स्तर पर कई व्यावहारिक समस्याओं के कारण एफआरएस ने देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने कठिनाई खड़ी की है। यह जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का एक और हथियार बन गया है। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने सरकार से इस असंतुलित नीति को वापस लेने की मांग की।

केंद्रीय कार्यसमिति ने फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में पुरी उड़ीसा में अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिसमें 42 औद्योगिक महासंघों और 28 राज्य इकाइयों के लगभग 2,500 चयनित प्रतिनिधि भाग लेंगे।

तवांग तीर्थ-यात्रा : भारत की आत्मा

भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बत की स्वाधीनता, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, हिमालय की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा एवं अन्य सम-सामयिक मुद्दों को लेकर अनवरत 26 वर्षों से कार्य कर रहा है। उपलब्धियों की दृष्टि से बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तवांग तीर्थ-यात्रा का आयोजन भी है। तवांग तीर्थ-यात्रा का आयोजन वर्ष 2012 में प्रारम्भ हुआ था। इस वर्ष 14वीं यात्रा 19 से 25 नवम्बर तक आयोजित होगी।

तवांग तीर्थ-यात्रा के सम्बन्ध में भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं तवांग तीर्थ यात्रा समिति के संयोजक पंकज गोयल जी ने कहा कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यात्रा में भारत की आत्मा रची-बसी हुई है। यह यात्रा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय एकता - अखंडता, सनातन बौद्ध समन्वय एवं देशभक्ति से ओतप्रोत है या यूँ कहें कि समग्र दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रा के माध्यम से संपूर्ण भारत के लोगों को पूर्वोत्तर भारत को जानने एवं समझने का अवसर प्राप्त होता है। यात्रा के प्रारंभ के समय यही भाव था कि सम्पूर्ण भारत के लोग पूर्वोत्तर भारत को ठीक से जानें एवं समझें। साथ ही पूर्वोत्तर के लोग भी राष्ट्र की मुख्यधारा से अपने को सदैव जोड़े रहें।

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बुमला बॉर्डर पर तवांग तीर्थ यात्री जाते हैं और वहां पहुँच कर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भारत माँ का पूजन एवं वंदन करते हैं। बुमला बॉर्डर पर पहुंच कर तीर्थ- यात्री धूर्त चीन को यह सन्देश देते हैं कि हम तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम हैं।

तवांग तीर्थ-यात्रियों के स्वागत- सम्मान में पूर्वोत्तर भारत के लोग अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। पूर्वोत्तर के लोगों की आत्मीयता, अपनत्व, अतिथि सत्कार की भावना, सरलता, मधुरता एवं मिलनसारिता तवांग तीर्थ-यात्रियों को बरबस ही आकर्षित कर लेती है। पूर्वोत्तर भारत के लोग जिस तरह से अपनी लोक कला, लोक संस्कृति एवं लोक व्यवहार को न सिर्फ बचाए हुए हैं,

बल्कि उसे और अधिक मजबूत करते जा रहे हैं, उससे सम्पूर्ण भारत को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी मिलती है। प्रकृति ने पूर्वोत्तर भारत पर खूब कृपा बरसाई है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखते ही बनते हैं। पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर जाने वाले तवांग तीर्थ -यात्रियों को ब्रह्मपुत्र नदी के टापू पर बना विश्व का एक मात्र शिव जी का मन्दिर, तेजपुर का महादेव मन्दिर, भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी का अग्निगढ़ मन्दिर, चित्रलेखा उद्यान, अरुणाचल का प्रवेश द्वार 'भालूक पोंग', पश्चिम कामेंग जिले का मुख्यालय 'बोमडिला', सैनिक जसवंत सिंह की स्मृति में बना जसवंतगढ़, भारत - चीन युद्ध के बलिदानियों का स्मारक, छठे दलाई लामा जी की जन्मस्थली 'तवांग मठ', दलाई लामा जी के पद चिन्ह, गुरु नानक देव जी की तपस्या स्थली भूमि पर बना 'नानक लामा'; जोगिन्दर बाबा का स्मारक सहित अन्य ऐतिहासिक स्थानों को देखने, जानने एवं समझने का अवसर मिलता है। प्रत्येक भारतवासी को सूर्य की धरती के रूप में सुविख्यात अरुणाचल प्रदेश के बुमला बॉर्डर तक की यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए। इससे पूरे राष्ट्र को जानने एवं समझने का अवसर मिलेगा।

संस्कृत के प्रचार-प्रसार में योगदान के लिए संस्कृत भारती के उपाध्यक्ष दिनेश कामत को अन्नपूर्णा श्री सम्मान

संस्कृत भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिनेश कामत जी को अन्नपूर्णा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर 51 वर्षों से पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में संस्कृत भाषा का मान बढ़ाया है। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्योत्सव एवं विश्व संस्कृत पुस्तक मेला को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया है। भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, न्यायिक अधिकारियों द्वारा संस्कृत में शपथ ग्रहण, प्रशासनिक पत्रों का लेखन एवं उद्बोधन में संस्कृत भारती का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके दृष्टिगत संस्कृत भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिनेश कामत जी को अन्नपूर्णा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के महामना सभागार में विद्वत् सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सभी विद्वानों को सम्मानित किया। सभी को सम्मान-पत्र, अंगवस्त्र, रुद्राक्ष माला तथा 51 हजार रु की राशि प्रदान की गई।

असम के राज्यपाल ने कहा कि आज भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। काशी की अतिप्राचीन शास्त्रार्थ परम्परा को उत्तरप्रदेश नागकूप शास्त्रार्थ समिति ने जीवन्त उत्सव बना दिया है। आज महनीय विद्वानों की उपस्थिति इस बात का बोध कराती है कि काशी शास्त्रार्थ की भूमि है, सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए शास्त्रों की रक्षा के लिए काशी में प्राचीन काल से शास्त्रार्थ होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं श्री काशी विद्वत्परिषद् के, जिनके मार्गदर्शन में काशी की शास्त्रार्थ परम्परा देश-दुनिया में नजीर बनकर उभरी है। आज पुनः काशी के मठ-मन्दिरों, गुरुकुलों तथा संस्कृत विद्यालयों में शास्त्रार्थ गूंजायमान हो रहा है। कार्य का आरम्भ वैदिक मंगलाचरण तथा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् सदस्य दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि आज का ये सम्मान सनातन धर्मावलम्बियों के लिए उदाहरण है। संस्कृत भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिनेश कामत ने कहा कि भारत की मातृभाषा संस्कृत भाषा होनी चाहिए। संस्कृत भाषा के उच्चारण के अनेकों लाभों पर उन्होंने प्रकाश डाला तथा अनेक अनुभवों को विद्वानों के समक्ष साझा किया। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री काशी विद्वत्परिषद् के अध्यक्ष पद्मभूषण प्रो. वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि संस्कृत भारत की आत्मा है, इसके बिना भारत के विश्वगुरुत्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सभी को पारम्परिक शास्त्रों की रक्षा करनी चाहिए। सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन तथा संयोजन श्री काशी विद्वत्परिषद् के राष्ट्रीय महामन्त्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने किया। स्वागत भाषण उत्तर प्रदेश नागकूप शास्त्रार्थ समिति के अध्यक्ष प्रो. सदाशिव द्विवेदी ने किया।

वार्ता से रास्ता निकले...

[अक्षय श्रीवास्तव]

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की यह उम्मीद कि आखिरकार अमेरिका और भारत साथ आएंगे, मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अच्छी बात यह है कि अमेरिका के एकतरफा टैरिफ और कुछ तीखे बयानों के बावजूद बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। वॉशिंगटन और नई दिल्ली, दोनों मिलकर इस मसले को सुलझा सकते हैं।

भड़काने वाले बयान

भारत पर थोपे गए ट्रंप के 50% टैरिफ को लेकर अमेरिका में साफ तौर पर दो विरोधी स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। एक धड़ा कूटनीतिक सीमाओं के इतर जाकर बयानबाजी कर रहा है और जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है। वहीं, दूसरे धड़े का मानना है कि रूस से तेल खरीदने के लिए केवल भारत को निशाना बनाना सही नहीं, जबकि सबसे बड़ा खरीदार चीन है। ऐसे माहौल में जरूरी है कि दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर संवाद जारी रहे। अच्छी बात यह है कि बेसेंट के मुताबिक, दोनों पक्ष मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं और मसले को सुलझाना चाहते हैं।

आपसी सहयोग जरूरी

भारत-अमेरिका का रिश्ता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। हाल के बरसों में दोनों ने सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा समेत दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया है। चीनी मनमानी पर नियंत्रण के लिए अमेरिका को खासतौर पर भारतीय सहयोग की जरूरत है। इसी मकसद से क्वॉड का गठन किया गया, जिसे अमेरिकी सरकार ने तवज्जो भी दी। लेकिन, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से क्वॉड के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, वॉशिंगटन में यह भी चिंता है कि पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका रिश्तों में जो प्रगति हुई थी, वह इन कुछ दिनों में बेकार हो गई।

दुनिया पर असर

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अमेरिका सबसे अमीर अर्थव्यवस्था। दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता है, तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिकी मांग के अनुसार, भारत अगर रूस से खरीदारी बंद भी कर देता है, तो इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई बाधित होगी और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। US इस पहलू को लगातार नजरअंदाज कर रहा है।

गतिरोध खत्म हो

दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार लगभग दोगुना हो गया है और इसे 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह तभी संभव है, जब मौजूदा गतिरोध खत्म हो। इसके लिए बातचीत ही रास्ता है। अड़ियल रुख अपनाने के बजाय अमेरिका को भारतीय नजरिया समझने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

जनजातीय विकास का नया युग

₹375.71 करोड़ स्वीकृत 100 पुल + अन्य निर्माण कार्य

9 मंत्रालय

11 प्रमुख विकास गतिविधियां

18 जिले

1442 गाँव

2,306 बसाहटें

56,669 परिवार

बचे 26 गांवों तक भी पहुंचेगी विकास की रोशनी

- **10,553** पक्के आवास पूर्ण
- **500** किमी सड़कें पूर्ण
- **44,101** आधार कार्ड जारी
- **10,125** किसान क्रेडिट कार्ड जारी
- **1,04,743** आयुष्मान कार्ड बने
- **36,521** जनधन खाते खुले
- **46,024** जाति प्रमाण पत्र जारी
- **228** गांवों में पाइप से जलापूर्ति
- **22,351** किसान सम्मान निधि पंजीकरण
- **30,559** राशन कार्ड वितरित
- **4,727** मातृत्व योजना लाभार्थी

- **4 छात्रावास** व **आंगनबाड़ी केंद्रों** का निर्माणकार्य पूर्ण
- बड़ी संख्या में **मोबाइल टॉवरों** की स्थापना
- **7 वन धन विकास केंद्र** संचालित
- **8 बहुउद्देशीय केंद्रों** का निर्माणकार्य पूर्ण

विद्युतीकरण

7144 परिवार (ऑन ग्रिड)

729 परिवार (ऑफ ग्रिड)

मोबाइल मेडिकल यूनिट

57 यूनिट से **317 गांव** लाभान्वित

* यह आंकड़े माह जुलाई तक के हैं कार्य निरंतर जारी है

हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे

हमसे जुड़ने के लिए **QR स्कैन करें**

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

RO. No. 13431/224